Regarding the condition of rural roads in Nandurbar Parliamentary Constituency

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी **(**नन्दुरबार**) :** माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के क्रियान्वयन तथा मेरे नन्दुरबार लोकसभा क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी बहुल, भौगोलिक रूप से दुर्गम, आर्थिक रूप से पिछड़ा और अत्यंत कमजोर संपर्क वाला जिला है । मैं ग्रामीण सड़कों की स्थिति से संबंधित विषय पर बात करना चाहता हूं ।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहता हूँ:-

क्या सरकार नन्दुरबार लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशेष पीएमजीएसवाई ग्रिड पैकेज को तात्कालिक रूप से स्वीकृत करेगी, ताकि सभी पहाड़ों को अनुसूचित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र ग्रिड-आधारित सड़क नेटवर्क से जोडा जा सकें? I am including for new roads and bridges as well as special repair programmes in PMGSY.

क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्र के लिए पीएमजीएसवाई के जनसंख्या मानदंड को 250 से घटाकर 100 करने पर विचार करेगी?

क्या सरकार पीएमजीएसवाई की सामग्री मानकों को उन्नत करेगी? विशेषकर, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में तथा SS1, RS1 इमल्शन के स्थान पर B2N, VG-30, VG-40 अथवा PMB का उपयोग अनिवार्य करेगी?

क्या मंत्रालय बिटुमिनस परतों के लिए हॉट मिक्स तकनीक को अनिवार्य करेगी, ताकि ग्रामीण सड़कों की समयपूर्व खराबी रोकी जा सके? विशेषकर, उन इलाकों में जहाँ ग्रामीण सड़कें भारी यातायात वहन करती हैं?

क्या सरकार मैकेनिक एम्पिरिकल डिजाइन, अनिवार्य सीबीआर परीक्षण, सॉयल स्टैबलाइजेशन, बेहतर ड्रेनेज और प्रदर्शन-आधारित रख-रखाव अनुबंधों को लागू करेगी?

क्या सरकार उन घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे नन्दुरबार में डिजिटल प्रणालियों के साथ अनिवार्य भौतिक निरीक्षण को लागू करेगी? There are forest clearances in my Shirpur *tehsil*, that is Batwapada area, pending for a very long time. I think that needs to be cleared.

सभापति महोदय, मेरा लास्ट पॉइंट यह है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं, लेकिन नन्दुरबार जैसे आदिवासी, पहाड़ी और बिखरे हुए जिले में सड़कें जीवन और मृत्यु, अवसर और उपेक्षा, पहुँच और वंचना के बीच का अंतर निर्धारित करती हैं । बिना सड़कों के कोई भी सरकारी योजना, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न रोजगार, न डिजिटल कनेक्टिविटी जनता तक नहीं पहुँच सकती ।

सभापति महोदय, अभी महाराष्ट्र में पीएमजीएसवाई फेज-4 चल रहा है और मध्य प्रदेश में पीएमजीएसवाई फेज-8 तक पहुंच गया है । महाराष्ट्र में भी पीएमजीएसवाई के फेज को बढ़ा दिया जाए । यह मैं विनती करता हूं । धन्यवाद ।